संस्करण ● नई दिल्ली ● पानीपत (हरियाणा) ● चण्डीगढ़ ●लखनऊ ● भोपाल (मध्य प्रदेश) ●हल्द्वानी नैनीताल ● देहरादून (उत्तराखण्ड) से एक साथ प्रकाशित... www.publicasia.in

पब्लिक की सुनें, पब्लिक की कहें

पब्लिक एशिया

@publicasia1989 @publicasiaofficial @publicasia e-mail: publicasia1989@gmail.com

वर्ष : 15, अंक : 280 पृष्ठ : 04, पानीपत, बुधवार 20 नवंबर 2024, मूल्य : 2 रूपये RNI No.- HARHIN/2011/40057

राजधानी में प्रदूषण का कहर एक्यूआई पहुंचा 494 के पार

एजेंसी

नई दिल्ली » राजधानी के लोगों का मंगलवार के दिन की शुरुआत भी स्मॉग की चादर के साथ हुई। तमाम कोशिशों और उपायों के बाद भी प्रदूषण ने लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 494 दर्ज किया गया। उत्तरी दिल्ली के कुछ इलाकों में एक्यूआई 500 के पार चला गया है। नॉर्थ कैंपस में एक्यूआई 500 दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली के आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और कई अन्य स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मंगलवार 450 के पार दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, कई ट्रेनें और उड़ानें विलंबित या रद्द कर दी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार सुबह कम से कम 22 ट्रेनें देरी से चलीं और नौ अन्य रद्द कर दी गईं।

अगर वायु गुणवत्ता की बात करें तो पूसा में 487, पंजाबी बाग में 481, आरकेपुरम में 477, वजीरपुर का 492, आनंद विहार में 500, डीटीयू में 496, द्वारका सेक्टर 8 में 486, आईटीओ में 386, जहांगीरपुरी में 500, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 481, लोधी रोड में 475, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम 489, मंदिर मार्ग में 480 और नजफगढ़ में 482 एक्यूआई पहुंच चुका है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है।

प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की आवश्यकता : गोपाल राय

नई दिल्ली » दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कृत्रिम बारिश कराने की आवश्यकता है। श्री राय ने इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र में कहा,' उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान हो या फिर बिहार ही क्यों न हो, आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है और आसमान पर धुंध की एक चादर फैली हुई है। वातावरण में मौजूद प्रदूषित कण बुजुर्गों और बच्चों की सांसों पर भारी पड़ रहा है और उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 की पाबंदियों लागू कर दी गई हैं। हम लगातार दिल्ली में प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।' उन्होंने कहा,'विशेषज्ञों से चर्चा के बाद यह बात सामने आई है कि अब वह समय आ गया है कि यदि हमें इस धुंध की चाटर को तोड़ना है तो हमें कृत्रिम वर्षा करवानी पड़ेगी।

दुष्कर्म मामले में अभिनेता सिद्दीकी को अग्रिम जमानत

एजेंसी

नई दिल्ली » उच्चतम न्यायालय ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को करीब आठ साल पहले कथित दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 2016 की कथित घटना के संबंध में इतनी देरी से 2024 में मुकदमा दर्ज करने पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि पीड़िता ने फेसबुक पर पोस्ट लिखने का साहस था, लेकिन उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया। अभिनेता सिद्दीकी पर एक युवा अभिनेत्री ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

आरोपी याचिकाकर्ता ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, केरल सरकार की ओर से रंजीत कुमार और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अभिनेता को राहत दी और अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली।

पीठ ने कहा कि वह मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जमानत के लिए विस्तृत कारण नहीं बता रही है। पीठ ने यह भी कहा कि कथित घटना 2016 में हुई थी और शिकायतकर्ता ने 2018 में कहीं फेसबुक पर पोस्ट करके कथित यौन शोषण के संबंध में अपीलकर्ता सहित 14 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे और यह भी कहा था कि वह केरल सरकार द्वारा गठित हेमा समिति के पास नहीं गई थी। सुनवाई के दौरान श्री रोहतगी ने कहा कि अभिनेता एक वरिष्ठ नागरिक हैं और 2016 की घटना के बारे में आठ साल बाद 2024 में शिकायत दर्ज की गई है।उन्होंने यह भी दावा किया कि अभिनेता ने महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने से एक दिन पहले 26 अगस्त, 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी।

शिष्टाचार भेंट

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मंगलवार को उनके सरकारी आवास पर फिल्म अभिनेता श्री विक्रांत मैसी जी ने शिष्टाचार भेंट की

मोदी ने महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

एजेंसी /नई दिल्ली » प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की । श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा, 'साहस और देशभक्ति की सच्ची प्रतिमूर्ति, निडर झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। आज़ादी की लड़ाई में उनकी बहादुरी और प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। विपरीत परिस्थितियों में उनके नेतृत्व ने दिखाया कि सच्चा दृढ़ संकल्प क्या होता है।' श्री मोदी इस समय जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रान्ति के दौरान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त किया।

मौसम

दिल्ली/एनसीआर

अधिकतम ता.	न्यूनतम ता.
26.0°C	15.0°C

संक्षिप्त समाचार

मणिपुर हिंसा : खड़गे का मुर्मु से हस्तक्षेप का आग्रह

एजेंसी

नई दिल्ली » कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मणिपुर की हिंसा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को मंगलवार को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और कहा कि डेढ़ साल से जारी हिंसा से लोगों का जीवन तबाह हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से वहां शांति बहाली होगी। श्री खरगे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर में हिंसा के कारण लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया है। राज्य में 540 से ज्यादा दिनों से हिंसा का तांडव चल रहा है और प्रधानमंत्री तथा राज्य के मुख्यमंत्री लोगों की समस्या को सुलझाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा,' राज्य में जारी हिंसा के कारण 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और एक दूसरे के खून के प्यासे लोग निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है।

सितंबर में ईएसआई योजना में 20.58 लाख कर्मचारी नामांकित

एजेंसी

नई दिल्ली » कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ईएसआई योजना में मौजूदा वर्ष के सितंबर में 20.58 लाख नये कर्मचारियों का नामांकन किया गया है जिनमें से 3.91 लाख महिला कर्मचारी हैं।श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मंगलवार को यहां बताया कि सितंबर, 2024 में 20.58 लाख नए कर्मचारी और 23,043 नए प्रतिष्ठान जोड़े गए।मंत्रालय ने बताया कि ईएसआई योजना में मौजूदा वर्ष के सितंबर में सितंबर 2023 की तुलना में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सितंबर 2024 में कुल कर्मचारियों में से, 10.05 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं, जो कुल पंजीकरण का लगभग 48.83 प्रतिशत है। सितंबर, 2024 में महिला सदस्यों का नामांकन 3.91 लाख रहा है।

विज्ञान और किसान के बीच की दूरी घटाने पर शिवराज का जोर

एजेंसी

नई दिल्ली » केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विज्ञान और किसान के बीच की दूरी घटाने पर जोर देते हुए कहा है कि किसान मिट्टी के सबसे बड़े संरक्षक हैं और उन्हें शिक्षा, प्रोत्साहन तथा आधुनिक वैज्ञानिक की जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाया जाना चाहिए।

श्री चौहान ने मंगलवार को यहां 'वैश्विक मृदा कॉफ्रेंस 2024' को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मिट्टी के सबसे बड़े संरक्षक हैं उन्हें शिक्षा, प्रोत्साहन और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। युवाओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि एक लाभदायक और सम्मानजनक पेशा है इसके लिए भी युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। छात्राओं और शोधकर्ताओं को स्थानीय और वैश्विक मृदा की चुनौतियों का समाधान करने वाले नवाचारों को विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिट्टी का क्षरण राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय है जो कि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। सम्मेलन में नीति आयोग के कृषि सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर वैज्ञानिक नवाचारों का समाधान और विस्तार प्रणालियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियां के सहयोग से भी किसानों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। विज्ञान और किसान के बीच की दूरी कम करनी होगी। 'लैब टू लैंड' - वैज्ञानिक से किसान तक समय पर सही जानकारी किसानों को मिलने का प्रयास किया जाना चाहिए।

वकीलों को ऑनलाइन पेश होने का विकल्प : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी

नई दिल्ली » उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के मद्देनजर पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करने की वकीलों की याचिका को मंगलवार को खारिज करते हुए कहा कि उनके (वकीलों) पास ऑनलाइन पेश होने का विकल्प होगा।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने %सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन% के अध्यक्ष कपिल सिब्बल और अन्य की दलीलें सुनने के कहा, 'हमने सभी जजों से कहा है कि जहां भी संभव हो वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दें।'

वकीलों ने पीठ के समक्ष दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढते प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। शीर्ष न्यायालय के समक्ष सिर्फ आनलाइन सुनवाई के पक्ष में दलील देते हुए श्री सिब्बल ने कहा, 'प्रदूषण नियंत्रण से बाहर हो रहा है।'न्यायालय ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि अदालत को पूरी तरह से ऑनलाइन होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वकीलों के पास ऑनलाइन पेश होने का विकल्प है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने श्री सिब्बल की दलीलों का समर्थन किया।सुप्रीम कोर्ट के समक्ष श्री मेहता ने कहा कि सिद्धांत रूप से शीर्ष अदालत को वर्चुअल होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा, 'आज हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन होना चाहता है, तो वह ऑनलाइन हो सकता है।'

सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक होगी भारत की आपराधिक न्यायिक प्रणाली : शाह

एजेंसी

नई दिल्ली » केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत की आपराधिक न्यायिक प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक और तेज गति वाली होगी। श्री शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।

गृह मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के बिना पुलिसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को प्रासंगिक रखना संभव ही नहीं है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस, अपराध के खिलाफ लड़ाई के हमारे पूरे तंत्र को प्रासंगिक रखने के लिए है। श्री शाह ने कहा,' हमें नए सिरे से इसके स्वरूप, सहभागिता, इनपुट्स लेने की पद्धति, अनुसंधान और विकास को पुलिस स्टेशन से नीचे बीट कॉस्टेबल तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की ज़रूरत है।' उन्होंने कहा कि इस पर समग्रता से विचार करने का समय आ गया है।

श्री शाह ने कहा कि कोई भी पद्धति 50 साल तक चलती है तो वह अप्रासंगिक हो जाती है। पिछले कई दशकों में देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं लेकिन क्या इनके अनुरूप पुलिस विज्ञान कांग्रेस का स्वरूप बदला है? उन्होंने, 'पुलिस विज्ञान कांग्रेस की कार्यपद्धति, उद्देश्यों और निर्णयों पर अमल में जो समयानुकूल परिवर्तन होना चाहिए, उसमें हम कहीं न कहीं पीछे हैं। आने वाले समय की चुनौतियों को समझे बिना हमारी योजना कभी सफल नहीं हो सकती।'

गृह मंत्री ने कहा,' पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व का हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है और इसके कारण हमारी चुनौतियां और बढ़ गई हैं।भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 11वें से पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और वर्ष 2028 से पहले हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुआ है।' केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान आठ सत्रों में - नए आपराधिक कानून, फॉरेंसिक विज्ञान का उपयोग, आपदा प्रबंधन, ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग, साइबर धोखाधड़ी, स्मार्ट सिटी में पुलिसिंग, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग और जेलों में कट्टरवाद से निपटने के उपायों - पर चर्चा होगी। अगले 10 वर्षों में भारत का आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक और तेज होगी। उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों पर पूरी तरह अमल होने के बाद किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक तीन वर्ष में न्याय मिल जाएगा। श्री शाह ने कहा कि दशकों से कश्मीर, उत्तरपूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र अशांत माने जाते थे लेकिन मोदी सरकार ने सुरक्षा स्थिति को सशक्त कर इन क्षेत्रों की स्थिति में बहुत सुधार किया है। उन्होंने कहा,'विगत 10 साल में हम इससे पहले के 10 साल की तुलना में हिंसा में लगभग 70 प्रतिशत की कमी लाने में सफल रहे हैं।

लोक सभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में आगामी शीतकालीन सत्र के लिए की गई व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

मुकेश वत्स, पब्लिक एशिया

नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज 18वीं लोक सभा के तीसरे सत्र अर्थात शीतकालीन सत्र से पहले संसद भवन परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस संबंध में, बिरला ने लोक सभा कक्ष, कॉरिडॉर, लॉबियों, प्रतीक्षा कक्षों, मीडिया सुविधाओं और अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया।

श्री बिरला ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संविधान दिवस, डॉ. बी.आर. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस और संसद पर हमले की वर्षगांठ शामिल है। इस वर्ष का संविधान दिवस इस मायने में खास है क्योंकि इस वर्ष भारत के संविधान को स्वीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है । उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। आगामी सत्र के दौरान स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के महत्व पर ज़ोर देते हुए, श्री बिरला ने सभी एजेंसियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने संसद भवन के भीतर आईटीडीसी द्वारा प्रदान की जा रही खानपान सेवाओं का निरीक्षण भी किया और संबंधित एजेंसियों को स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्री बिरला ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को माननीय सदस्यों के लिए संसद तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया।

सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 24 नवंबर को

सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को पारंपरिक सर्वदलीय बैठक बुलायी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि बैठक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के परिप्रेक्ष्य में बुलायी गयी है।

आम निवेशकों का माधवी बुच के नेतृत्व वाले सेबी से घट रहा है विश्वास : राहुल

एजेंसी

नई दिल्ली » कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की विश्वसनीयता को इसकी प्रमुख माधवी बुच के कारण धक्का लग रहा है और इसकी वास्तविकता की पड़ताल को लेकर वह विभिन्न क्षेत्र के प्रमुख लोगों से समय-समय पर बात करते हैं।

कांग्रेस नेता ने आज कहा कि इस एपीसोड में उन्होंने पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा तथा अनुभवी पत्रकार सुचेता दलाल के साथ गहन विचार विमर्श किया है जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि श्रीमती बुच के नेतृत्व में आम निवेशकों का सेबी पर विश्वास घट गया है।

श्री गांधी ने कहा, 'बुच स्टॉप्स हियर% के इस एपिसोड में, मैंने पवन खेड़ा और अनुभवी पत्रकार सुचेता दलाल के साथ बैठकर चर्चा की है कि किस तरह एकाधिकार को बढ़ावा देने वाली प्रणाली द्वारा खुदरा निवेशकों को कुचला जा रहा है। यह बातचीत माधबी बुच के नेतृत्व में सेबी की विफलता पर प्रकाश डालती है, जहां आम निवेशक की सुरक्षा के लिए बने नियामक तंत्र अब अडानी जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों की सुरक्षा कर रहे हैं। यह केवल वित्तीय कुप्रबंधन के बारे में ही नहीं है बल्कि इसमें यह भी विमर्श हुआ कि कैसे छोटे निवेशक, उद्यमी और ईमानदार व्यवसाय उस प्रणाली में विश्वास खो रहे हैं जो निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।'

उन्होंने कहा,'साथ मिलकर, हम साठगांठ वाले पूंजीवाद की वास्तविक कीमत का विश्लेषण करते हैं - खोई हुई बचत के संदर्भ में ही नहीं बल्कि लाखों मेहनती भारतीयों के लिए विश्वास और अवसर के क्षरण के संदर्भ में भी विचार करते हैं। यदि हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को होने वाली क्षति अपरिवर्तनीय होगी। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम सच्चाई को उजागर करेंगे और एक निष्पक्ष तथा अधिक न्यायपूर्ण भारत के लिए लड़ेंगे।'

आलेख

धधक रहा है मणिपुर ... बुझाए कौन

मणिपुर में हिसा की मौजूदा घटना कोई नया नहीं है। पिछले डेढ़ साल (566 दिन) से यह प्रदेश हिंसा की लपटों में धधक रहा है और केंद्र तथा राज्य की सरकार मौन ओढ़े हुए हैं। सरकारी आँकड़ों पर भरोसा करें तो छोटे से उस राज्य में हिंसा की घटनाओं में अबतक 220 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कई महिलाओं की आबरू लूटी गई और हजारों करोड़ की संपत्ति आग के हवाले कर दी गई। बता देना जरूरी है कि मणिपुर में भाजपा की चुनी हुई सरकार है लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार असहाय दिखाई देती है। आमलोगों की कौन कहे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सरकारी आवास और पैतृक घर पर दो बार हमला और आगजनी की घटनाएँ हो चुकी हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो मणिपुर में मैतेई, कुकी और नगा का वर्चस्व है। राज्य में सर्वाधिक आबादी मैतेई समुदाय की है। उनकी संख्या लगभग 65 फीसदी है, जबकि कुकी और नगा मिलाकर कुल आबादी का 35 फीसदी हैं। समुदायों के बीच टकराव मणिपुर के लिए नया नहीं है। 90 के दशक में मणिपुर में कुकी और नगा समुदाय के बीच संघर्ष हुआ था। तब सैकड़ों लोगों की जान गई थी। बड़ी मुश्किल से तब हिंसा की आग बुझाई जा सकी थी।

राधा रमण

वर्तमान में मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष छिड़ा है। इसका कारण मैतेई समुदाय की आरक्षण की माँग है। मैतेई काफी दिनों से इसकी माँग कर रहे हैं। चूंकि मणिपुर की पहाड़ियों पर बसने वाले कुकी और नगा समुदाय के लोग अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हैं और उन्हें इसका लाभ भी मिलता रहा है लेकिन मैतेई इस लाभ से वंचित हैं। यही वजह है कि मैतेई समुदाय के लोगों ने आरक्षण की माँग को तूल दिया। जबकि कुकी और नगा समुदाय के लोगों का कहना है कि मैतेई समुदाय के लोगों की पहले से विकास योजनाओं में अधिक भागीदारी रही है और उन्हें इसका लाभ मिलता रहा है। इसलिए उनके लिए अलग से आरक्षण की माँग बेमानी है। अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण का लाभ मिला तो वे राज्य के संसाधनों के साथ-साथ सरकारी नौकरियों पर भी काबिज हो जाएँगे। ऐसे में कुकी समुदाय के लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। इस विवाद ने तूल उस समय पकड़ लिया जब मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वह मैतेई समुदाय को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। इससे पहले कि राज्य सरकार केंद्र को मैतेई समुदाय को आरक्षण के दायरे में लाने का प्रस्ताव भेजती कुकी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए। मैतेई समुदाय के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो सड़कों पर हिंसा का रौरव तांडव शुरू हो गया।

इसके अलावा मणिपुर में हिंसा की दूसरी वजह का वह कानून है जिसमें कहा गया है कि मैतेई समुदाय के वह लोग जो घाटी में बसे हैं वह पहाड़ी इलाकों में न तो घर बना सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं। इसके उलट कुकी और नगा समुदाय के लोग घाटी में जमीन खरीद सकते हैं और घर बनाकर बस भी सकते हैं। मैतेई समुदाय के लोग इसका पहले से विरोध करते रहे हैं। वह एक राज्य एक कानून के तहत पहाड़ियों पर जमीन की खरीद का अधिकार चाहते रहे हैं।

मणिपुर की उस जघन्य घटना से पूरा देश मर्माहत और शर्मसार है जिसे पिछले साल 4 मई को अंजाम दिया गया था। उस घटना में दो महिलाओं को कपड़े उतारकर सड़कों पर घुमाया गया, सरेआम पीटा गया और गैंगरेप किया गया था। हैरत की बात यह कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले उस घटना के दरिंदों पर कार्रवाई करने, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की बजाय सरकारी मशीनरी ने उस घटना को ही छुपा लिया। जब दो महीने बाद उस घटना का वीडियो वायरल हुआ तब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यह कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया कि समाज में इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं। मामला तूल पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वत» संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि मणिपुर मामले में 'कुछ कीजिए, वरना हम करेंगे'।

तब से लेकर आजतक मणिपुर लगातार सुलगता रहा है। बीच-बीच में हिंसक झड़पों की रिपोर्ट आती रहती है। राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बल्कि यह कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि मणिपुर के हालात पर पर्दा डाला जाता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने संसद के भीतर और बाहर कई दफा प्रधानमंत्री से मणिपुर मामले में हस्तक्षेप करने और वक्तव्य देने की माँग की। राहुल मणिपुर के शरणार्थी कैंप भी गए और उसमें रह रहे लोगों से बातचीत की लेकिन दुखद बात यह कि विपक्ष की लगातार माँग के बावजूद प्रधानमंत्री ने मणिपुर जाने की बात तो दूर, इस मामले पर अबतक मुँह नहीं खोला है।

मणिपुर में हिंसा की ताजा वारदात 11 नवंबर को सुरक्षाबलों से मुठभेड़ में 10 बंदूकधारी उग्रवादियों के मारे जाने के बाद हुई। कुकी समुदाय ने मारे गए लोगों को विलेज गार्ड बताया और मुठभेड़ के जिम्मेदार सुरक्षाबलों पर कार्रवाई की माँग की। इसे संयोग कहें या प्रयोग कि उसी दिन जिरीबाम से दो महिलाओं समेत 6 लोगों का अपहरण कर लिया गया। अपहरण का आरोप कुकी उग्रवादियों पर लगाया गया। इसमें एक महिला जो तीन बच्चों की माँ थी, सामूहिक दरिंदगी कर उसके शरीर में कीलें ठोंक दी गई और उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। इंसानियत को शर्मसार कर देनेवाले इस घटना से डॉक्टर भी हैरान हैं। पोस्टमार्टम करनेवाले डॉक्टरों ने इसे वीभत्स और दिल दहलाने वाला कृत्य बताया। रिपोर्ट लिखे जाने तक सभी अपहृत लोगों के शव बरामद कर लिये गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण है। केंद्र सरकार ने मणिपुर के पाँच जिलों इंफाल पूर्व और पश्चिम, थोबल, विष्णुपुर और काकचिंग में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है और सात जिलों में इंटरनेट सेवाएँ अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया है।

मणिपुर में हिंसा से हरकत में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महाराष्ट्र का अपना चुनावी दौरा छोड़कर दिल्ली पहुँचे। केंद्र सरकार ने छह थाना क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) लागूकर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा शांति बहाली के लिए सुरक्षाबलों को पूरी छूट दे दिया है। साथ ही मामले की जाँच के लिए एनआईए को सौंप दिया है। साथ ही सुरक्षाबलों की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजी है। इस बीच दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए हैं। कुकी समुदाय के लोगों ने जहाँ मारे गए कथित उग्रवादियों का शव सौंपने के लिए पोस्टमार्टम हाउस पर जोरदार प्रदर्शन किया जबकि मैतेई समुदाय के लोग राज्य के छह विधायकों और तीन मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की तथा आग लगाने का प्रयास किया जिसे सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज कर और आँसू गैस के गोले छोड़कर नाकाम किया। फिर भी मुख्यमंत्री के दामाद और भाजपा विधायक का घर फूंक दिया गया।

इस बीच, भाजपा के 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री को पत्र भेजकर राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार को बदलने की माँग की है। माँग करनेवालों में मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष सत्यव्रत भी शामिल हैं। उधर, सरकार में शामिल रहे नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने एन बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। विधानसभा में एनपीपी के 7 विधायक हैं। हालाँकि विधानसभा में भाजपा को अकेले दम पर बहुमत हासिल है। इसके अलावा उसे छह और विधायकों का समर्थन हासिल है। इसलिए फिलहाल सरकार पर अस्थिरता का संकट नहीं है।

उधर, मणिपुर सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर राज्य से अफस्पा हटाने की माँग की है। देखना जरूरी होगा कि मणिपुर पर केंद्र सरकार आगे क्या कदम उठाती है। फिलहाल तो मणिपुर धधक रहा है और प्रधानमंत्री नाइजीरिया का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रहण कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। *- राधा रमण*

सही दिशा देने से हर बच्चा हो सकता है चैंपियन

स्वाती वर्मा

बाल मजदूरी से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता ही है, देश भी इससे अछूता नहीं रहता क्योंकि जो बच्चे काम करते हैं वे पढ़ाई-लिखाई से कोसों दूर हो जाते हैं और जब ये बच्चे शिक्षा ही नहीं लेंगे तो देश की बागडोर क्या खाक संभालेंगे? इस तरह एक स्वस्थ बाल मस्तिष्क विकृति की अंधेरी और संकरी गली में पहुँच जाता है और अपराधी की श्रेणी में उसकी गिनती शुरू हो जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसी जगह काम करते हैं जो उनके लिए असुरक्षित और खतरनाक होती है जैसे कि माचिस और पटाखे की फैक्टरियां जहां इन बच्चों से जबरन काम कराया जाता है। इस दिन लोगों को बाल अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके लिए दुनियाभर में संगोष्ठी भी आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष यूनिसेफ विश्व बाल दिवस की थीम निर्धारित करता है।

सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर पर विशेष

भारत में हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। हालांकि नवंबर माह में एक नहीं बल्कि दो बार बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर का बाल दिवस मनाया जा चुका है। ये दिन जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर बच्चों को समर्पित करते हुए मनाते हैं। हालांकि एक ही महीने में दो बार बाल दिवस मनाने की एक खास वजह है। इस दिन का इतिहास और उद्देश्य 14 नवंबर के बाल दिवस से अलग है।

विश्व बाल दिवस मनाने की शुरुआत 1954 से हुई। पहली बार सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर 1954 को मनाया गया। उसके बाद से यह दिन बाल दिवस के लिए निर्धारित हो गया और प्रतिवर्ष इस दिन सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाने लगा। विश्व भर में बच्चों के बीच जागरूकता लाने तथा बच्चों के कल्याण में सुधार लाने के लिए मनाया जाता है ये विश्व बाल दिवस।

क्या वजह है कि नवंबर में दो बार बाल दिवस मनाने के पीछे की क्या है वजह ? दरअसल, बच्चे भारत के हों या दूसरे देशों के वह समाज और राष्ट्र का भविष्य होते हैं। एक देश आगे चलकर कैसा रूप लेगा, ये सम्पूर्ति रूप से आने वाले बच्चो पर निर्भर करता है। लिंग, जाति, धर्म, विकलांगता, यौन अभिविन्यास या अन्य स्थिति के बावजूद, हर बच्चा जश्न मनाने का हकदार है और उसे सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ शामिल होने और संरक्षित होने का अधिकार है।

जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से लेकर, नस्लवाद और भेदभाव को समाप्त करने के लिए, बच्चे और युवा लोग उन मुद्दों पर अपनी आवाज उठा रहे हैं जो उनकी पीढ़ी के लिए मायने रखते हैं और वयस्कों को बेहतर भविष्य बनाने का आह्वान कर रहे हैं। बच्चों की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य को लेकर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में भी बाल दिवस मनाया जाता है। दूसरा बाल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा के साथ मनाने की शुरुआत की। 14 नवंबर के अलावा दूसरा बाल दिवस विश्व स्तर से हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं लेकिन एक दौर में भारत में भी 20 नवंबर ही बाल दिवस के लिए निर्धारित किया गया था।

साल 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन अपनाया था। 20 नवंबर को ही बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की वर्षगांठ होती है। इसलिए इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य भी कर रहे हैं। यूनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) भी बाल विकास और कल्याण की दिशा में कार्य कर रहा है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। इसके लिए देश के स्वर्णिम विकास के लिए बच्चों का विकास बहुत जरूरी है। बच्चे अपने भविष्य को कैसे एक बेहतर रूप दे सके इस पर और अपने मन व इच्छा अनुसार अपने लिए अपना करियर का चुनाव कर सके। यूनिसेफ लगातार इसके लिए प्रयासरत है। बाल मजदूरी से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता ही है, देश भी इससे अछूता नहीं रहता क्योंकि जो बच्चे काम करते हैं वे पढ़ाई-लिखाई से कोसों दूर हो जाते हैं और जब ये बच्चे शिक्षा ही नहीं लेंगे तो देश की बागडोर क्या खाक संभालेंगे? इस तरह एक स्वस्थ बाल मस्तिष्क विकृति की अंधेरी और संकरी गली में पहुँच जाता है और अपराधी की श्रेणी में उसकी गिनती शुरू हो जाती हैं। कुछ बच्चे ऐसी जगह काम करते हैं जो उनके लिए असुरक्षित और खतरनाक होती है जैसे कि माचिस और पटाखे की फैक्टरियां जहां इन बच्चों से जबरन काम कराया जाता है।

इस दिन लोगों को बाल अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। इसके लिए दुनियाभर में संगोष्ठी भी आयोजित की जाती है। प्रतिवर्ष यूनिसेफ विश्व बाल दिवस की थीम निर्धारित करता है। इस साल विश्व बाल दिवस 2024 की थीम 'हर बच्चे के लिए, हर अधिकार' (For Every Child, Every Right) है जो कि ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों का आह्वान करता है कि सभी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हों। इसमें शिक्षा, भोजन, आवास, स्वच्छता और हानिकारक काम से सुरक्षा का अधिकार शामिल है। माता-पिता, शिक्षक, नर्स और डॉक्टर, सरकारी नेता और नागरिक समाज के कार्यकर्ता, धार्मिक और सामुदायिक बुजुर्ग, कॉर्पोरेट मुगल और मीडिया पेशेवर, साथ ही युवा लोग और बच्चे, विश्व बाल दिवस को उनके लिए प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज, समुदाय और राष्ट्र। विश्व बाल दिवस हममें से प्रत्येक को बच्चों के अधिकारों की वकालत करने, बढ़ावा देने और जश्न मनाने, संवादों और कार्यों में अनुवाद करने के लिए एक प्रेरणादायक प्रवेश-बिंदु प्रदान करता है जो बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करेगा।

बाल अधिकारों के लिए अपना समर्थन प्रदर्शित करने के लिए जागरूक और छोटे, मगर महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए यूनिसेफ हर किसी को आमंत्रित करता है और लगातार इस कार्य के प्रति काम कर रहा है साथ ही लोगो को जागरूक भी। शिक्षा, लिंग समानता, स्वच्छता और पीने के पानी तक पहुंच, बाल श्रम समाप्त करने सहित हर बच्चे को हर अधिकार दिलाने में मदद करने के लिए और भारत में बाल विवाह की समाप्ति के अलावा, भारतीय बाल अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए यूनिसेफ लगातार प्रयासरत है। यदि बच्चों का होगा सही विकास,तभी देश का भी होगा विकास।

युवाओं को सशक्त बनाना; भारत की नई इंटर्नशिप योजना गेम चेंजर क्यों है ?

भारत का नौकरी बाजार तेजी से आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के कारण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई पीएम इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य 21-24 वर्ष की आयु के उन लोगों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके व्यापक कौशल अंतर को पाटना है जो न तो नियोजित हैं और न ही पूर्णकालिक शिक्षा में हैं। 56 प्रतिशत से अधिक नियोक्ताओं को अगली छमाही में कार्यबल विस्तार की उम्मीद है, यह पहल सही समय पर आई है। यह अधिक तैयार, नौकरी के लिए तैयार कार्यबल बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जो नवाचार और दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि दोनों को बढ़ावा देता है। वास्तविक दुनिया का अनुभवः नौकरी के लिए तैयार उम्मीदवारों को आकार देना शैक्षणिक योग्यता और नौकरी की तैयारी के बीच बढ़ता अंतर वर्षों से भारत के श्रम बाजार में एक प्रमुख चुनौती रही है। कई स्नातकों के पास सैद्धांतिक ज्ञान तो है लेकिन आज के तेज़ गति वाले उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण व्यावहारिक कौशल का अभाव है। नई इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया के कार्य वातावरण में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके इस अंतर को पाटना है। यह दृष्टिकोण उन्हें उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए कौशल से लैस करेगा, जिससे अधिक सक्षम और अनुकूलनीय कार्यबल तैयार होगा। केवल तकनीकी कौशल से परे, इंटर्नशिप छात्रों को समय सीमा का प्रबंधन करना, टीमों के साथ सहयोग करना और कॉर्पोरेट संस्कृति को नेविगेट करना सिखाती है। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स में एक पूर्ण-स्टैक डेवलपर को न केवल कोडिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, बल्कि टीम वर्क, समय प्रबंधन और ग्राहक समझ की भी आवश्यकता होती है। इंटर्नशिप उस व्यावहारिक अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक चरण हैं। हाल ही में टीमलीज़ एडटेक सर्वेक्षण के अनुसार, 72 प्रतिशत नियोक्ताओं ने 2024 में फ्रेशर्स को नियुक्त करने की योजना बनाई है, जिसमें ई-कॉमर्स, इंजीनियरिंग और रिटेल जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक मांग है। इन क्षेत्रों में इंटर्नशिप से छात्रों की रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे पहले दिन से ही नौकरी के लिए तैयार हैं। अन्वेषक संवारना» समस्या-समाधानकर्ताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करना इंटर्नशिप योजना के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक युवा पेशेवरों के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करने की क्षमता है। तेजी से बदलते नौकरी बाजार में, आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम प्रशिक्षुओं को गतिशील कार्य वातावरण में रखता है जहां उन्हें पहल करने, समस्याओं को हल करने और लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है - प्रमुख गुण जो नियोक्ता आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में तलाश रहे हैं। प्रशिक्षु अक्सर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ लेते हैं जिनके लिए उन्हें निर्णय लेने, छोटी परियोजनाओं का नेतृत्व करने और अनुभवी पेशेवरों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है। यह अनुभव उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें नए दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वरिष्ठ पेशेवरों से मार्गदर्शन के साथ, प्रशिक्षु नेतृत्व गुणों में भी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। नतीजतन, कार्यक्रम न केवल वर्तमान नौकरियों के लिए प्रशिक्षुओं को तैयार करता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की वृद्धि को आगे बढ़ाने में सक्षम समस्या-समाधानकर्ताओं की एक पीढ़ी का पोषण भी करता है। रोजगार के लिए निर्बाध परिवर्तन आजकल नियोक्ता ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास न केवल शैक्षणिक योग्यता है बल्कि व्यावहारिक अनुभव भी है। इंटर्नशिप छात्रों को उद्योग मानकों और अपेक्षाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करके इस अंतर को पाटती है। यह अनुभव प्रशिक्षुओं को नौकरी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देता है, जिससे अक्सर पूर्णकालिक रोजगार मिलता है। इसके अलावा, नियोक्ता अक्सर इंटर्नशिप को भविष्य में नियुक्तियों के लिए एक पाइपलाइन के रूप में देखते हैं, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले इंटर्न को अक्सर स्थायी पदों की पेशकश की जाती है। यह कम हो जाता हैव्यवसायों के लिए भर्ती का समय और लागत। यह इंटर्नशिप को एक जीत की स्थिति बनाता है, कंपनियों को पूर्व-प्रशिक्षित प्रतिभा और छात्रों को वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करता है। छात्रों के लिए, इंटर्नशिप केवल उद्योग ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है; वे संचार, टीम वर्क और समस्या-समाधान जैसे सॉफ्ट कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। औपचारिक शिक्षा में अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले ये कौशल आज के तेजी से बढ़ते नौकरी बाजार में महत्वपूर्ण हैं। जैसे-जैसे भारत का रोजगार परिदृश्य विकसित हो रहा है, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के संयोजन वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता केवल बढ़ेगी। आगे का रास्ता नई इंटर्नशिप योजना सिर्फ एक शैक्षणिक पहल नहीं है; यह एक व्यापक रणनीति है जिसका उद्देश्य भारत के नौकरी बाजार को बदलना है। वास्तविक दुनिया के अनुभव पर जोर देकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और पूर्णकालिक रोजगार के लिए एक निर्बाध पुल बनाकर, कार्यक्रम उन कई चुनौतियों का समाधान करता है जो परंपरागत रूप से भारत के युवाओं की रोजगार क्षमता में बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे-जैसे अधिक छात्र व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे और आज के नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक कौशल विकसित करेंगे, भारत का कार्यबल अधिक प्रतिस्पर्धी, अनुकूलनीय और अभिनव बन जाएगा। इससे न केवल व्यक्तिगत छात्रों को बल्कि नियोक्ताओं को भी लाभ होगा, जो अगले तीन वर्षों में भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दृष्टिकोण में योगदान देगा।

विजय गर्ग

लेखकः सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

पुरुषों के अस्तित्व एवं सुरक्षा की मांग क्यों उठने लगी?

ललित गर्ग

महिला से ही बनता घर है पर पुरुष घर का सहारा है। महिला से स्वर्ग है महिला से बैकुंठ, महिला से ही चारों धाम है पर इन सब का द्वार तो पुरुष ही है। उन्हीं पुरुषों के सम्मान में पुरुष दिवस मनाया जाता है। दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत भी घरेलू हिंसा की समस्या से जूझ रहा हैं। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून भी बने हैं, लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई सरकारी अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिससे इस बात का पता लग सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की तादाद कितनी है।

दुनिया में अब महिला दिवस की भांति पुरुष दिवस प्रभावी रूप में बनाये जाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। अब पुरुष भी अपने शोषण एवं उत्पीडित होने की बात उठा रहे हैं। महिलाओं की ही भांति अब पुरुषों पर भी उपेक्षा, उत्पीड़न एवं अन्याय की घटनाएं पनपने की बात की जा रही है। महिला दिवस की तर्ज पर ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाने लगा है। पहला अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 1999 में 19 नवंबर को डॉ. जेरोम टीलकसिंह ने त्रिनिदाद और टोबैगो में मनाया था। पुरुष दिवस दुनिया के 30 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'सकारात्मक पुरुष रोल मॉडल' है। यह ऐसा एक वैश्विक उत्सव है जो पुरुषों के सकारात्मक योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाता है, साथ ही पुरुषों के स्वास्थ्य, कल्याण और लैंगिक समानता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दिन पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने वाली चर्चाओं और कार्यों को बढ़ावा देने, सकारात्मक रोल मॉडल को प्रोत्साहित करने और अधिक समावेशी समाज की वकालत करने का अवसर प्रदान करता है।

कुछ वर्ष पूर्व भारत में सक्रिय अखिल भारतीय पुरुष एशोसिएशन ने भारत सरकार से एक खास मांग की कि महिला विकास मंत्रालय की भांति पुरुष विकास मंत्रालय का भी गठन किया जाये। इसी तरह यूपी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने यह मांग उठाई थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसी भी एक संवैधानिक संस्था बननी चाहिए। इन सांसदों ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। पत्र लिखने वाले एक सांसद हरिनारायण राजभर ने उस वक्त यह दावा किया था कि पत्नी प्रताड़ित कई पुरुष जेलों में बंद हैं, लेकिन कानून के एकतरफा रुख और समाज में हंसी के डर से वे खुद के ऊपर होने वाले घरेलू अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। प्रश्न है कि आखिर पुरुष इस तरह की अपेक्षाएं क्यों महसूस कर रहे हैं? लगता है पुरुष अब अपने ऊपर आघातों एवं उपेक्षाओं से निजात चाहता है। तरह-तरह के कानूनों ने उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को धुंधलाया है। जबकि आज बदलते वक्त के साथ

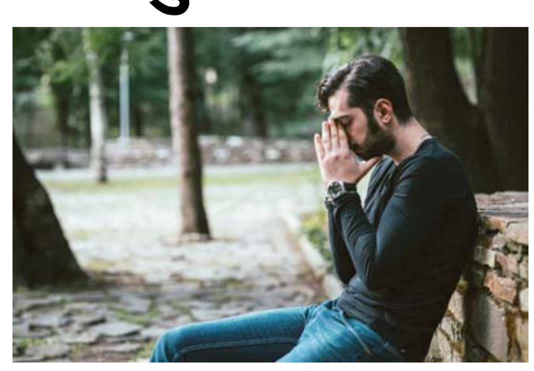

पुरुष अब अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील हो चुका है। कई युवा पुरुष समाज-निर्माण की बड़ी जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं और अपनी काबिलीयत व जुनून से यह साबित भी कर रहे हैं।

आज का पुरुष सिर्फ खुद को नहीं बल्कि महिलाओं के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ता है। वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि उन्हें भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें व उन्हें किसी भी भेदभाव का सामना न करना पड़े। यह परिवर्तन आज सभी इंडस्ट्री जैसे मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, उद्योग, व्यापार आदि में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां महिलाएं शीर्ष पदों पर काम कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं पुरुषों को अब महिलाओं के नेतृत्व में कार्य करने में भी झिझक नहीं महसूस होती। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस दिवस को मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया और पुरजोर सराहना एवं सहायता दी है। एक तरफ जहां महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वहीं पुरुषों की भी छवि समाज में बदलती जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व की बात करें तो पुरुषों को लेकर समाज में ढेरों रुढ़िवादी विचार थे, महिलाओं के शोषण एवं उसे दोयम दर्जा दिये जाने का आरोप उस पर लगता रहा है। जिनमें अब तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। पुरुष एक ऐसा शब्द जिसके बिना किसी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारी जहां जीवन को परिपूर्णता देती है तो वहीं पुरुष ही इसका आधार है। नारी जन्मदात्री है तो पुरुष जीवन-निर्माता है। भारतीय समाज में 'मर्द को दर्द नहीं होता' या फिर जब कोई पुरुष रोता है तो 'मर्द बनो और रोना बंद करो' जैसी बातें बोली जाती हैं। पिछले कई सालों से पुरुषों की समाज में संघर्षशील व कठोर छवि को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन मुख्य सवाल है कि आखिर मर्द या पुरुष हैं कौन? जो घोड़े दौड़ाता है, शिकार करता है, या फिर जो अच्छे सूट में, चमचमाती कार में ऑफिस जाता है और घर पर भी अपनी तारीफ ही सुनना चाहता है। एक रौबदार छवि, आक्रांता, शोषक, असंवेदनशीलता एवं अत्याचारी वाली उसकी छवि क्या वास्तविक छवि है? असल में पिछले कुछ वर्षों में मर्द की परिभाषा में एक उदारवादी एवं संवेदनशील बदलाव देखने को मिला है। अब पुरुष या मर्द वो नहीं जो हमें अब तक पूर्वाग्रही रूढ़िवादी मानसिकता बताती हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा वो है ऐसा आधारस्तंभ है जो जिम्मेदारी उठाता है, जो सिर्फ चमकदार जूते एवं कपड़े ही नहीं पहनता बल्कि समाज व देश को भी चमकदार बनाने के लिए आगे आता है, परिवार की जिम्मेदारियों को ढोता है।

अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो पुरुषों और लड़कों की चुनौतियों और अनुभवों को पहचानने और उनका समाधान करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक पुरुषत्व और लैंगिक समानता के बारे में बातचीत को प्रोत्साहित करता है। पुरुषों के मुद्दों को संबोधित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लैंगिक समानता एक सामूहिक प्रयास है, जिससे पुरुष और महिला दोनों को लाभ होता है, तथा पुरुषों की भलाई पर ध्यान देना इस यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। समाज रूपी गाड़ी को सही से चलाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि महिलाएं उसका विरोधी होने के बजाय सहयोगी बने। उन्हें किसी भी भेदभाव का सामना न करना पड़े। मानवीय रिश्तों में दुनिया में सबसे बड़ा स्थान मां के रूप में नारी को दिया जाता है, लेकिन एक बच्चे को बड़ा और सभ्य बनाने में उसके पिता के रूप में पुरुष का योगदान कम करके नहीं आंका जा सकता। महिला ममता का सागर है पर पुरुष उसका किनारा है।

पब्लिक एशियाः पत्र पंजीकरण संख्याः HARHIN/2011/40057, स्वामी मुकेश वत्स के लिए मुद्रक, प्रकाशक, स्वाति वर्मा ने पब्लिक एशिया E- 33, सैक्टर-7 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित करवाकर कार्यालय पब्लिक एशिया हाउस, शॉप नो.-8 ईदगाह रोड, नियर रेलवे स्टेशन, मॉडल टाउन, पानीपत, 132103, हरियाणा से प्रकाशित किया से प्रकाशित किया। E-mail: publicasia1989@gmail.com, website: www.publicasia.in, स्वाति वर्मा (संपादक), मुख्य कार्यालय : पब्लिक एशिया हाऊस 686 जी, न्याय खंड 2 इंद्रापुरम गाज़ियाबाद(उ.प्र)। Mobile No. 8287879604, 9891945513, 0120-2605513 इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होगें।
वैधानिक सूचना-पाठकों को सलाह दी जाती है की किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन में प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच- पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उपरोक्त विज्ञापन के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

मुख्य समाचार

जाट कॉलेज के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया

प्रधान श्री गुलाब सिंह दिमाना ने प्रतिभागियों को दी शुभकामनाएं

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » यूथ फेस्टिवल 2024-25 में विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभागी बने और विजेता रहे जाट कॉलेज के विद्यार्थियों को जाट शिक्षण संस्था के प्रधान श्री गुलाब सिंह दिमाना ने शुभकामनाएं दी। जाट कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में श्री दिमाना ने प्रतिस्पर्धाओं के इंचार्ज शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों का बहुआयामी विकास होता है। उन्होंने कहा कि विजेता विद्यार्थियों को कॉलेज द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। जाट कॉलेज की प्राचार्या डॉ. शबनम राठी ने बताया कि तीन दिवसीय यूथ फेस्टिवल में कॉलेज के विद्यार्थियों ने 25 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 11 पुरस्कार जीते। उन्होंने बताया कि पुरुष वर्ग के सोलो डांस और मिमिक्री में प्रथम और महिला वर्ग के सोलो डांस में द्वितीय और पंजाबी भाषा कविता पाठ में कॉलेज को तीसरा स्थान मिला। वहीं रंगोली में तीसरा स्थान रहा। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान, कोलॉज में तृतीय, हिंदी डिबेट पक्ष-विपक्ष में द्वितीय व तृतीय स्थान जाट कॉलेज के नाम रहा। उन्होंने बताया कि ग्रुप डांस हरियाणवी, ग्रुप सोंग हरियाणवी, फोक सोंग, स्किट, गजल और सामान्य ग्रुप सोंग में भी हमारे विद्यार्थियों को बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इस अवसर पर प्राचार्या डॉ. शबनम राठी, डॉ. सरोज नारा, डॉ. सरोज बाला, डॉ. मुनीष नांदल, डॉ. महिमा, डॉ. नीरा, डॉ. सीमा, डॉ. मनीषा दहिया, डॉ. रेखा, डॉ. सुधा के अलावा सभी प्रतिभागी विद्यार्थी उपस्थित रहे।

बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर तीन ड्रोन बरामद किये

एजेंसी

जालंधर » सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने लगातार ड्रोन की तलाश जारी रखते हुए आज तरनतारन और अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में तीन और पाकिस्तानी ड्रोन जब्त किये। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि एक डीजेआई माविक 3 क्लासिक ड्रोन को बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त सर्च दल ने सुबह करीब 07 :12 बजे तरनतारन जिले के गांव-वान से सटे एक खेत से तलाशी अभियान के बाद बरामद किया। दूसरा डीजेआई मैट्रिस 300 आरटीके ड्रोन बीएसएफ जवानों ने सुबह करीब 08 :30 बजे सीमा बाड़ से आगे तरनतारन जिले के गांव-नौशेरा ढाला से सटे एक खेत से टूटी हुई हालत में बरामद किया।प्रवक्ता ने बताया कि एक और डीजेआई माविक 3 क्लासिक ड्रोन को सतर्क बीएसएफ जवानों ने अमृतसर जिले के गांव राजाताल के समीप सीमा पर बाड़ के आगे एक खेत से सुबह करीब 10 :42 बजे बरामद किया है। माना जा रहा है कि सीमा पर तैनात तकनीकी जवाबी उपायों के समय पर सक्रिय होने के कारण इन ड्रोन को मार गिराया गया।

9 से 16 दिसंबर तक गोवा में आयोजित होगी अखिल भारतीय सिविल सेवा फुटबॉल पुरुष खेल प्रतियोगिता

पब्लिक एशिया ब्यूरो

रोहतक » उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा वर्ष 2024-25 अखिल भारतीय सिविल सेवा फुटबॉल पुरुष खेल प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 16 दिसंबर 2024 तक गोवा में करवाया जाएगा। हरियाणा राज्य की फुटबॉल खेल की पुरुष टीम के चयन के लिए पानीपत में 28 नवंबर 2024 को ट्रायल करवाया जाएगा। धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि इस चयन ट्रायल में हरियाणा राज्य के सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भाग ले सकते है। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी अपने विभाग से फोटो सहित प्रमाण पत्र लेकर आए तथा अपने सत्यापित जन्म प्रमाण पत्र तथा विभाग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र संख्या साथ लेकर निर्धारित तिथि 28 नवंबर को सुबह 10 बजे निर्धारित स्थान पर पहुंचे। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड की हिदायतों के अनुसार इन सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में बोर्ड, कारपोरेशन के अधीन कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी तथा पुलिस विभाग, बिजली बोर्ड, एचएसआईडीसी के कर्मचारी व अधिकारी भाग नहीं ले सकते है।

राज्य की टीम के चयन के लिए 28 नवंबर को पानीपत में होगा ट्रायल

बॉक्स » अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टेनिस प्रतियोगिता का 15 से 21 दिसंबर तक राजस्थान में होगा आयोजन » उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा आगामी 15 से 21 दिसंबर 2024 तक राजस्थान के जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में अखिल भारतीय सिविल सेवा लॉन टैनिस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के महिला व पुरुष टीमों के लॉन टैनिस टीमों के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसके लिए 27 नवंबर को पंचकुला में ट्रायल के माध्यम से खिलाडि़यों का चयन किया जाएगा।

डीएपी पर अधिकारी सरकार को या सरकार किसानों को कर रही है गुमराह : सैलजा

एजेंसी /चंडीगढ़, » कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि डीएपी संकट पर या तो अधिकारी नायब सिंह सैनी सरकार को गुमराह कर रहे हैं या फिर सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। कुमारी सैलजा ने यहां जारी बयान में कहा कि डीएपी पर सरकार लगातार दावे कर रही है कि डीएपी की कमी नहीं है और विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है लेकिन डीएपी उपलब्धता का संकट नहीं है तो फिर सरकार यह बताये कि हरियाणा में किसान पूरे-पूरे दिन कतार में क्यों खड़े हैं? और इसके बावजूद उन्हें डीएपी क्यों नहीं मिल रहा।

रोहतक में सरकारी संपत्ति पर लगे पोस्टर स्टिकर का मामला उठा विधानसभा में

स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत के स्लोगन का उल्लंघन है शहरों की सुंदरता खराब करना : बत्तरा

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » विधायक भारत भूषण बत्तरा ने आज विधानसभा में शहर के सौंदर्य को खराब कर रहे सरकारी संपत्तियों और चौराहों पर लगे पोस्टर स्टीकरों का मामला प्रमुखता से उठाया! उन्होंने कहा कि सरकार इसकी रोकथाम कैसे करेगी इस बारे में जवाब दें और इस पर सख्त कानून बनाए! विधानसभा में आज कॉलिंग अटेंशन मोशन पर बोलते हुए भारत भूषण बत्तरा ने कहा पूरे प्रदेश में करोड़ों स्टीकर सरकारी संपत्तियों और सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे हुए हैं! रोहतक शहर के ही प्रमुख मानसरोवर पार्क के गेट पर बहुत शानदार मार्बल लगा हुआ है, जो पोस्टर और स्टीकरों की वजह से बर्बाद हो रहा है। मानसरोवर पार्क हो या डबल पार्क हो उनका सौंदर्य करण इसलिए किया जाता है कि लोगों को अच्छा लगे लेकिन इन स्टीकर पोस्ट की वजह से वह पूरी तरीके से खराब हो जाता है! सरकारी कॉलेज की दीवारें गेट दूर-दूर तक भरे पड़े होते हैं पोस्टर और स्टीकर से! चौक चौराहे की बात की जाए या महापुरुषों की प्रतिमाओं के लिए बने चौक की, कोई जगह अछूती नहीं है जहां पोस्टर स्टीकर की वजह से बुरा हाल ना हो!

उन्होंने कहा कि शहर के एलिवेटेड पुलों के नीचे और ऊपर हर जगह दूर-दूर तक पोस्टर और स्टीकर नजर आते हैं! बत्तरा ने कहा कि ऐसी स्थिति एक दिन में नहीं हुई , सालों से यह पोस्टर स्टीकर लगे हुए हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं , कोई उन्हें साफ नहीं करता ! उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति का बुरा हाल होता है उसकी शेप ही बदल जाती है! सरकार द्वारा दिए गए स्लोगन स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत का यह पूरी तरह से उल्लंघन है।

बत्तरा ने कहा कि सरकार हिदायत जारी करें कि जो भी पोस्टर, या स्टीकर लगते हैं, उनके नीचे प्रिंटर का नाम और नंबर जरूर लिखा होना चाहिए! उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के लिए लगाए जाने वाले फ्लेक्स से ज्यादा घातक है स्टिकर और पोस्टर जो स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं! उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में न केवल वार्निंग जारी करें बल्कि जुर्माना भी तय करें ! उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह एक बार तो पूरे शहर को साफ करवा दें! इसके साथ ही सरकार इसकी रोकथाम कैसे करेगी इस बारे में जवाब भी दे और इस पर सख्त कानून भी बनाएं! बॉक्स एक्सटेंशन लेक्चरर्स का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने उठाया बत्तरा ने एक्सटेंशन प्रथा ,ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए »भारत भूषण बत्तरा सदन की कार्यवाही में भाग लेते हुए भारत भूषण बत्तरा ने कहा एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो लगे हैं यह किसकी कमी है,क्यों नहीं नियमित भर्ती होती? उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि आज आप उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं ,हम किसी की नौकरी के खिलाफ नहीं है,उन्होंने कहा कि विभाग के पास अगर इतनी पोस्ट है तो आप उन सब का एक अलग विंग भी बना सकते हैं ,जिसमें कोई टेस्ट वगैरह लेकर उनकी अप्वाइंटमेंट्स कर सके! बत्तरा ने कहा कि यह 1500 लेक्चरर एक्सटेंशन लेक्चरर्स है, इनमें न कोई मेरिट चेंज होती है, जिसने जिसकी सिफारिश कर दी उसको लगा दो! कोई स्क्रीनिंग नहीं कोई पारदर्शिता नहीं साक्षात्कार के लिए एक प्रिंसिपल ही अप्वॉइंट करता है! ना उसका कोई विज्ञापन निकाला जाता! सरकार 56700 रूपए इस समय उन्हें तनख्वाह दे रही है सरकार उन्हें रेगुलर स्केल ही दे दे! सरकार उन्हें पूरा नौकरी का फायदा तो दे! बत्तरा ने कहा कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज के एक्सटेंशन लेक्चरर्स को,तो,पूरा,कर,दिया, विश्वविद्यालय में कार्यरत लेक्चरर्स का क्या कसूर है? विश्वविद्यालय में कार्यरत 1500 लेक्चरर्स की पोस्ट तो विज्ञापित की गई थी! उनकी एप्लीकेशन ली जाती है उनकी स्कूटनी की जाती है उसके बाद भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर है! पर उसकी तनख्वाह सरकार देती है विश्वविद्यालय नहीं देता! उन्होंने कहा कि एक कानून लाया जाए जब इनका कर दिया तो उनका भी किया जाना चाहिए वह भी 10-10 साल से लगे हुए हैं! उनको भी रेगुलर किया जाना चाहिए! वे वेल क्वालिफाइड हैं सभी साक्षात्कार प्रक्रिया उन्होंने पूरी की है! उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि विश्वविद्यालय के 1500 लेक्चरर्स का भी भला करें! बत्तरा ने कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए! उन्होंने कहा कि यह ठेका पर था एक्सटेंशन प्रथा बंद होनी चाहिए !इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। कठोर कानून बनाने और शहर को साफ करवाने का मंत्री विपुल गोयल ने दिया आश्वासन विभाग के मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर वे रोहतक और पूरे हरियाणा में सफाई अभियान शुरू करेंगे ! विपुल गोयल ने कहा कि भारत भूषण बत्तरा ने जो चिंता की है वह जायज है! उन्होंने कहा कि 1989 में एक्ट बना लेकिन उसमें और ज्यादा संशोधन करने की आवश्यकता है! उन्होंने कहा कि इस बारे में सामाजिक संस्थाएं और पॉलिटिकल पार्टियों को भी जागरूक होना पड़ेगा! विभाग ने बड़ी संख्या में पोस्टर बैनर हटाए भी है लेकिन इसे और बेहतर किया जाएगा! विपुल गोयल ने कहा कि जल्द ही सभी के सहयोग से एक कठोर कानून बनाकर लाया जाएगा।

जीवन में स्वच्छता को धारण करना बहुत जरूरी : शालिनी चेतल

विश्व शौचालय दिवस पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल ने नवनियुक्त ग्राम सचिवों, कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

पब्लिक एशिया ब्यूरो

रोहतक » जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शालिनी चेतल ने कहा कि जीवन में स्वच्छता को अपनाना बहुत जरूरी है। अपने आसपास परिवेश में स्वच्छता बनाए रखने से जहां एक तरफ पर्यावरण शुद्ध रहता है, वहीं दूसरी तरफ हम निरोगी रह सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती चेतल मंगलवार को स्थानीय विकास भवन परिसर में नव चयनित ग्राम सचिवों और अपने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को विश्व शौचालय दिवस पर अपना संदेश दे रहीं थी। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई और स्वच्छता को अपने जीवन में धारण करने का संदेश दिया।

स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए सीईओ जिला परिषद श्रीमती चेतल ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोडक़र माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। उन्होंने शपथ दिलाई कि हम स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे और उसके लिए समय देंगे। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करेंगे। हम न गंदगी करेंगे और ना किसी और को करने देंगे। शपथ » सबसे पहले में स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करेंगे।

हम मानते हैं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि यहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ हम गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करेंगे। स्वयं के साथ-साथ अन्य 100 व्यक्तियों से भी कवाएंगे। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करेंगे। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया हमारा यह एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। प्रशिक्षण ले रहे नवनियुक्त ग्राम सचिवों को संदेश देते हुए श्रीमती चेतल ने कहा कि वे अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह समझें। गांवों की विकासपरक योजनाओं की बारीकी से जानकारी लें। इस दौरान कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

सकारात्मक सोच बनाएं खिलाड़ी : डॉ. आरपी गर्ग

खेल को खेल की भावना से ही खेलें खिलाड़ी : प्रधान श्री गुलाब सिंह दिमाना

जाट कॉलेज के बॉस्केटबाल चैंपियनशिप का समापन हुआ

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » जाट कॉलेज के बॉस्केटबाल मैदान पर सोमवार को इंटर कॉलेज बॉस्केटबाल चैंपियनशिप का समापन हुआ। समापन के दौरान मुख्य अतिथि मदवि के स्पोटर्स डायरेक्टर डॉ. आरपी गर्ग व विशिष्ट अतिथि जाट शिक्षण संस्था के प्रधान श्री गुलाब सिंह दिमाना रहे। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का कॉलेज प्राचार्या डॉ. शबनम राठी व कॉलेज के शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष डॉ. सुखबीर सिंधु ने स्वागत किया। डॉ. आरपी गर्ग ने खिलाडि़यों को मदवि द्वारा खिलाडि़यों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को शुरुआती चरण में ही तकनीकी रूप से मजबूत होने की जरुरत है, तभी वो राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। डॉ. गर्ग ने कहा कि सकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा बढ़ाती है। एक अच्छा खिलाड़ी अपने खेल के प्रति दिलचस्पी, उत्सुकता और सीखने की चाह रखता है। वह अपना खेल लगन से खेलता है, उसका अपने खेल पर नियंत्रण होता है और वह हारी हुई बाजी को भी जीतने का हौसला रखता है।

जाट शिक्षण संस्था के प्रधान श्री गुलाब सिंह दिमाना ने विजेता टीम को प्रोत्साहन के रूप में 5100 रुपए की नकद राशि दी। उन्होंने कहा कि जीत और हार खेल के दो पहलू हैं और खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल खेलने से मनुष्य का शारीरिक विकास व मानसिक विकास होता है और खिलाडि़यों को खेल हमेशा बिना किसी द्वेष भावना के खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हर आम व्यक्ति को अपने व्यस्त समय में से थोड़ा बहुत समय खेलों में भी लगाना चाहिए। प्राचार्या डॉ. शबनम राठी ने खिलाडि़यों का हौंसला बढ़ाते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि खेल में हार जीत तय है हारे हुए टीम को निराश नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। डॉ. राठी ने कहा कि निरंतर अभ्यास करने वाला खिलाड़ी ही जीवन में सफल होता है। एक खिलाड़ी को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई के साथ-साथ खेल की महता भी बढ़ गई है। कॉलेज के बॉस्केट बाल टीम के कोच डॉ. नीतेश लठवाल ने बताया कि आज हुए फाईनल मुकाबले में जाट कॉलेज और यूटीडी के बीच फाईनल मैच हुआ जिसमें यूटीडी की टीम ने 78-60 अंकों से जीत हासिल करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं दूसरे मुकाबले में गवर्नमेंट कॉलेज बादली ने सीआरए सोनीपत को 68-60 अंकों से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस अवसर पर डॉ. सुरेश मलिक, डॉ. नीतेश लठवाल, डॉ. वरुण मलिक, डॉ. मनीष हुड्डा, डॉ. राम, डॉ प्रतीक धनखड़ सहित सभी शारीरिक शिक्षा विभाग के प्राध्यापक मौजूद रहे।

पंचायतों से सौ सौ गज के प्लॉट आवंटन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित : कृष्ण लाल पवार

ग्रामीण वस्तियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जरूरत पर बजट भी बढ़ाया जाएगा

पब्लिक एशिया ब्यूरो

चंडीगढ़ । हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश की पंचायतों से सौ सौ गज के प्लॉट आवंटन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम बस्ती योजना के तहत आबाद बस्तियों में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और इसके लिए जरूरी हुआ तो सरकार से बजट बढ़ाने की मांग की जाएगी। पवार सदन में इनेलो सदस्य आदित्य देवीलाल चौटाला के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 'महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना 2008 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परंतु विभिन्न कारणों से कुछ लाभार्थियों को आवंटित किए गए प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया जा सका था। वर्तमान सरकार द्वारा स्थापित किए गए हॉउसिंग फॉर ऑल विभाग के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत गत 10 जून 2024 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 7,000 लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को आवंटित प्लॉटो का कब्जा शीघ्र अति शीघ्र देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पंवार ने बताया कि 'महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना' के तहत कई लाभार्थियों को प्लॉट आंवटित नहीं हो सके थे जिसे ध्यान में रखते हुए हॉउसिंग फॉर ऑल विभाग के द्वारा 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार' का शुभारम्भ किया गया जिसके तहत भूमिहीन ग्रामीण परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को तीव्र गति से लागू करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 1,000 ग्राम पंचायतों को चिंहित भी किया जा चुका है एवं इन पंचायतों ने पात्र परिवारों को पंचायती भूमि में से प्लॉट काटने का प्रस्ताव भी पास करके राज्य सरकार को दिया है।

उन्होंने बताया कि जहां तक महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत स्थापित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, गलियां और नालियां उपल्ब्ध करवाने का प्रश्न हैं, इसके लिए सरकार निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अतंर्गत लगभग 4,573 कॉलोनियों को निर्मित किया गया तथा इनमें से लगभग 2,250 कॉलोनियों में, जहां बसावट शुरू हो गई हैं, वहीं मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी गई हैं।

पिछले दस वर्षों में इस योजना के तहत लगभग 320.50 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट में से बिजली विभाग को लगभग 94.50 करोड़ रूपये तथा जन स्वास्थ्य विभाग को लगभग 66 करोड़ रूपये मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवंटित किए गए हैं। सरकार के इन प्रयासों में और अधिक तीव्रता लाने के लिए 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी करते हैं, और इसमें जन स्वास्थ्य, पंचायत राज और बिजली विभाग के उप-मंडल अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस विशेष टास्क फोर्स की मुख्य भूमिका इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण करना, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से सिफारिशें प्रदान करना है। इसमें प्राथमिकता उन कॉलोनियों को दी जाती है जहां पर्याप्त आबादी बस चुकी है, और इस विशेष टास्क फोर्स को सक्रिय करने के लिए कई अवसरों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पंवार ने सिरसा जिला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 269 बस्तियां स्थापित की जा चुकी हैं , इनमें से 113 बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं और 156 बस्तियों में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।उन्होंने यह भी बताया कि सरकार बुनियादी ढांचा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोई भी इस योजना की कॉलोनी, जो इन सुविधाओं से अभी तक वंचित है, उसे इस योजना के तहत आवश्यक विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।'

नए चुने गए पंच गांव के विकास के लिए प्रेरक का कार्य करे : भगवंत मान

पब्लिक एशिया ब्यूरो

चंडीगढ़ » पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को प्रदेश की नई चुनी गई पंचायतों से अपील की कि वे अपने गांवों को %आधुनिक विकास केंद्रों% में बदलने के लिए प्रेरक के तौर पर काम करे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।संगरूर जिले के नए चुने गए पंचों को पद की शपथ दिलाने से पहले एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को अपने गांवों के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटना चाहिए ताकि राज्य सरकार काम शुरू करवा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंचायतें गांवों के समग्र विकास के लिए प्रस्ताव पारित करें जिसके लिए राज्य सरकार उनके हर प्रयास में सहयोग करेगी। उन्होंने नए चुने पंचों को गांव वासियों की तरक्की व खुशहाली यक़ीनी बनाने के साथ-साथ अपने गांवों को विकास के केंद्र में तब्दील करने के लिए नए कदम उठाने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती हैं और नए चुने पंचों को पद की शपथ दिलाना ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के 19 जिलों में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य के 10031 नए सरपंचों को लुधियाना में 8 नवंबर को हुए समारोह के दौरान पद की शपथ दिलाई गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता द्वारा चुना जाना गर्व की बात है क्योंकि यह लोगों में नेता के प्रति विश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो जनता द्वारा इन नेताओं पर सौंपी जाती है, क्योंकि यह जनता की सेवा का महान कार्य है। भगवंत सिंह मान ने नव-निर्वाचित पंचों को आश्वासन दिया कि गांवों में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना कर रही है, जो राज्य के विकास और खुशहाली का केंद्र बनेंगी। इस अनुकरणीय पहल का उद्देश्य युवाओं में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि गांवों को भी ऐसी पुस्तकालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित करने चाहिए, क्योंकि यह कदम युवाओं को सशक्त बनाने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्य समाचार

जाट कॉलेज ने शूटिंग में पाया द्वितीय स्थान

दिमागी विकास के लिए दमदार खेल है शूटिंग : प्रधान श्री दिमाना

सुकरमपाल, पब्लिक एशिया

रोहतक » गट एंड गेटस अकादमी में इंटर कॉलेज महिला वर्ग की शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें अखिल भारतीय जाट सूरमा स्मारक महाविद्यालय की महिला वर्ग की शूटिंग टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को जाट शिक्षण संस्था के प्रधान श्री गुलाब सिंह दिमाना और कॉलेज प्राचार्या डॉ. शबनम राठी ने बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान मदवि के खेल डायरेक्टर डॉ. आरपी गर्ग ने भी खिलाडियों को बधाई देते हुए हौंसला बढ़ाया। प्रधान गुलाब सिंह दिमाना ने कहा कि शूटिंग खेल से बुद्धि का विकास होता है। शूटिंग खेलने से खिलाड़ी के अंदर एकाग्रता यानी फोकस को बढ़ाता है। श्री दिमाना ने कहा कि कम उम्र से अगर इस खेल को खेला जाए तो इसके परिणाम काफी अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा कि शूटिंग का खेल आपको प्लानिंग, विश्वास, अनुशासन भी सिखाता है। प्राचार्या डॉ. शबनम राठी ने खिलाडियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शूटिंग खेल भावना सिखाता है। उन्होंने कहा कि शूटिंग एक ऐसा खेल है जिसे हर उम्र के लोग आसानी से सीख सकते हैं और जो प्रेरणा बढ़ाता है, व्यवहार को सुधारने में मदद करता है, आत्मविश्वास और भागीदारी विकसित करता है। कोच डॉ. वरुण मलिक ने बताया कि शूटिंग प्रतियोगिता में कॉलेज के खिलाडियों दृष्टि, कौशल राज, अंजलि, काजल मलिक, सहदेव और रवि ने शानदार प्रदर्शन कर कॉलेज को दूसरा स्थान दिलाया। उन्होंने विजेता खिलाडियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉ. सुरेश मलिक, डॉ. वरुण मलिक, डॉ. नितेश लठवाल सहित शारीरिक शिक्षा विभाग के सभी प्राध्यापक मौजूद रहे।

मंडल रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला 21 नवंबर को

प्रदीप गौतम, पब्लिक एशिया

गुरूग्राम,। मण्डल रोजगार कार्यालय गुरूग्राम द्वारा 21 नवंबर को प्रातः 9 बजे लघु सचिवालय स्थित पांचवी मंजिल पर कमरा नम्बर 513-514 पमें रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेले में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, फाइव फोर्स सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड व स्विगी इंस्टामार्ट लिमिटेड आदि कम्पनियां भाग ले रही है, जिनमें 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट पास बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

मोहिंदर भगत ने जालंधर में 5443 नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई

एजेंसी

जालंधर » पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने मंगलवार को यहां जंडियाला गांव के खेल स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह के दौरान जिले की नवनिर्वाचित 890 ग्राम पंचायतों में से 5443 पंचों को पद की शपथ दिलाई। श्री भगत ने कहा कि पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाने में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि ये पंचायत चुनाव राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिह्न के बिना करवाये गये हैं, ताकि गांवों को राजनीतिक गुटबाजी की छाया से दूर रखा जा सके। इस कदम से लोगों में आपसी भाईचारा और मजबूत होगा। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचों से अपील की कि वे अपने-अपने गांवों में ग्राम पंचायतें करके पंचायत के फैसले में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में 195 पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई हैं, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की भावना और मजबूत हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और राज्य के कई मंत्रियों ने भी पंचायत चुनावों से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और आज उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायत सदस्यों से गांवों के विकास के लिये धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने, विशेष रूप से पंचायत निर्णयों में अत्यधिक पारदर्शिता के लिये ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने का आग्रह किया।

एआईपीईएफ यूटी बिजली विभाग के निजीकरण कदम के खिलाफ सामूहिक सम्मेलन में भाग लेगा

एजेंसी

चण्डीगढ़ » ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बिजली कर्मियों के समर्थन में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) के बैनर तले 22 नवंबर को चंडीगढ़ यूटी बिजली विभाग के निजीकरण कदम के खिलाफ सामूहिक सम्मेलन में भाग लेगा। एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने मंगलवार को बताया कि महासचिव रत्नाकर राव और पड़ोसी राज्यों के बिजली इंजीनियर भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। श्री दुबे ने कहा कि वह निजीकरण के खिलाफ लड़ाई में चंडीगढ़ के बिजली कर्मियों के साथ खड़े हैं। ऐसी ही स्थिति में एआईपीईएफ के हस्तक्षेप के बाद पुडुचेरी में बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया रोक दी गयी। विद्युत अधिनियम की धारा 133(2) कर्मचारियों को किसी भी स्थानांतरण योजना के तहत कम अनुकूल सेवा शर्तों पर कर्मचारियों को स्थानांतरित न करने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। महासचिव रत्नाकर राव ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 131 के तहत इस तरह के प्रावधान के अभाव में प्रशासन सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रहा था। इसके अलावा, विभाग मुनाफे में चल रहा था और इसका राजस्व पिछले तीन वर्षों से अधिशेष था और सभी तकनीकी मानक अच्छे हैं, फिर भी इसका निजीकरण किया जा रहा है। बिजली क्षेत्र के इंजीनियर और कर्मचारी निजीकरण की आड़ में बिजली कर्मचारियों की सेवा शर्तों से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे।

हरियाणा के हकों के लिए समूचा सदन एकजुट

मुख्यमंत्री नायब सैनी और स्पीकर हरविंदर कल्याण ने किया आश्वस्त

पंजाब के सभी दलों के नेता राबी ब्यास नदियों के जल में हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का विरोध करते रहे है। इसके चलते करीब चार दशकों से एस वाई एल कैनाल का निर्माण लंबित है।

नईम खान, पब्लिक एशिया

चंडीगढ़ » चंडीगढ़ और नदी जल में हरियाणा के हक के लिए समूची विधानसभा एकजुट है।शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को सदन में यह मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्पीकर हरविंदर कल्याण ने यह आश्वासन दिया। सदन के सत्र की आखिरी दिन की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य अशोक अरोड़ा ने यह मुद्दा उठाया। अरोड़ा ने तुरंत खड़े होकर कहा कि पंजाब के नेताओं की ओर से ऐसे बयान आए है कि जैसे चंडीगढ़ पर हरियाणा का कोई हक ही नहीं है।इसी तरह एस वाई एल का पानी रोका गया है।उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। सरकार इस पर बयान दे।

अरोड़ा ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलकर दखल की मांग की जाए। विपक्ष इस मामले में सरकार के साथ है।अरोड़ा के इस तरह मुद्दा उठाने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी खड़े हो गए।उन्होंने कहा कि हरियाणा के हितों को

लेकर समूचा हरियाणा एकजुट है। इस मुद्दे पर एकजुट होकर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा

कि हरियाणा के हितों के लिए सभी एकजुट है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा के अलग विधान भवन के निर्माण के लिए पंचकूला से लगते चंडीगढ़ की सीमा पर दस एकड़ जमीन आवंटित करने का पंजाब के नेता विरोध कर रहे है।पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इसके विरोध में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा है।

इतना ही पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने भी हरियाणा को अलग विधान भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने का विरोध किया है। पंजाब के सभी दलों के नेता राबी ब्यास नदियों के जल में हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने का विरोध करते रहे है।इसके चलते करीब चार दशकों से एस वाई एल कैनाल का निर्माण लंबित है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कैनाल निर्माण के लिए हरियाणा के पक्ष में नवंबर 2016में ही आदेश दे चुका है।

100 नेत्र विशेषज्ञों ने तीसरे चंडीगढ़ आई फिल्म फेस्टिवल 2024 सीएमई में लिया भाग

पब्लिक एशिया ब्यूरो

चण्डीगढ़ » अपने वार्षिक आयोजन के क्रम में सिटी आई बैंक द्वारा चंडीगढ़ ऑपथैल्मोलॉजी सोसायटी के तहत में डॉ. अशोक शर्मा कॉर्निया सेंटर, चंडीगढ़ के सहयोग से तीसरा चंडीगढ़ आई फिल्म फेस्टिवल 2024 सीएमई का आयोजन होटल शिवालिक व्यू में किया गया। इस सीएमई में क्षेत्र के लगभग 100 नेत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इस सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर के एडवांस आई सेंटर के पूर्व डीन और प्रमुख पद्मश्री प्रोफेसर आमोद गुप्ता ने किया। प्रोफेसर आमोद गुप्ता ने 'विज्ञान में नैतिकता पर चौराहे पर' विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने नेत्र विशेषज्ञों को चेताया कि वे नए आविष्कारों या नई शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को सावधानी से न अपनाएं। उन्होंने सलाह दी कि हम सभी को चिकित्सीय विकल्प का चयन करते समय रोगी को कोई नुकसान नहीं होने के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

प्रोफेसर जगत राम, डॉ एम आर डोगरा, प्रोफेसर एस एस पांडव, प्रोफ़ेसर सुरेश गुप्ता, डॉ पी एस धामी, डॉ रंजीत एस धालीवाल, डॉ संदीप महाजन, प्रोफ़ेसर राम लाल, प्रोफ़ेसर गौरव शर्मा, प्रो राजीव तुली और प्रो अनिल वर्मा ने अपने प्रस्तुतीकरण और चर्चाओं के ज़रिए प्रतिभागियों को ज्ञान प्रदान किया। युवा नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा चुनौतीपूर्ण मामलों पर कंपीटिटिव सेशन और 2 मिनट के वीडियो सेशन कांफ्रेंस के अन्य मुख्य पहलू थे।

डॉ. अशोक शर्मा, निदेशक कॉर्निया सेंटर चंडीगढ़ जो मुख्य आयोजन सचिव थे, ने शिशुओं और बच्चों में कॉर्निया ग्राफ्टिंग पर अपना ववर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बच्चों में 250 से अधिक सफल कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक है।

डॉ. राजन शर्मा ने स्क्लेरोकोर्नियल रिंग्स से लिम्बल स्टेम सेल कल्चर्स पर अपना शोध प्रस्तुत किया और इसके नैदानिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। डॉ. अशोक शर्मा का कॉर्निया सेंटर कॉर्निया ट्रांसप्लांट, लिम्बल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और जटिल कॉर्निया रोगों के उपचार के लिए जाना जाता है। कांफ्रेंस का संचालन बेंगलुरु, कर्नाटक के प्रसिद्ध रेटिनल सर्जन डॉ. के.एस. कुमार ने किया।

यह अनोखा तीसरा वार्षिक आयोजन था जिसका उद्देश्य वीडियो आधारित प्रस्तुतियों और चर्चाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना था। वैज्ञानिक कार्यक्रम को प्रतिनिधियों को अपने प्रश्न पूछने और संवादात्मक चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एक बार जब नेत्र विशेषज्ञ इस ज्ञान को अपने रोगियों के उपचार में लागू करेंगे तो विचार-विमर्श से क्षेत्र में नेत्र देखभाल में सुधार होगा।

हरियाणा में अवैध ढंग से लगाए पोस्टर हटाने के लिए सरकार चलाएगी मेगा अभियान

कानून को भी संशोधित करने की जरूरत : गोयल

पब्लिक एशिया ब्यूरो

चण्डीगढ़ » हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने मंगलवार को विधानसभा में ऐलान किया कि जल्दी ही प्रदेश स्तर पर मेगा अभियान चलाकर सार्वजनिक संपत्ति पर लगाए गए पोस्टर और स्टीकर आदि हटाए जाएंगे और उनका सौंदर्य बहाल किया जाएगा।गोयल ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण रोकने के लिए हालांकि कानून मौजूद है लेकिन इस कानून में संशोधन की जरूरत महसूस की गई है। उन्होंने कहा कि कानून को और सख्त बनाया जाएगा।पोस्टर और अन्य प्रचार सामग्री पर प्रिंटर के नाम और फोन नम्बर प्रिंट करना अनिवार्य किए जाएंगे।

गोयल सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के मुद्दे पर कांग्रेस सदस्य बीबी बत्रा,गीता भुक्कल और आफताब अहमद द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे।प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बत्रा ने कहा कि पोस्टर और स्टीकर लगाकर सार्वजनिक संपत्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है।इस स्थिति पर सरकार का ध्यान नहीं है।सरकारी स्कूल,फ्लाई ओवर और पार्क के गेट पर पोस्टर लगा दिए जाते है।उन्होंने उदाहरण के बतौर कहा कि इंदौर एवं चंडीगढ़ में इस तरह पोस्टर नही लगाए जाते।सरकार इन्हें हटवाने और रोकने के लिए कदम उठाए।

गीता भुक्कल ने कहा कि सौंदर्यीकरण सूची में हरियाणा के एक भी शहर का नाम नहीं है।पोस्टर और स्टीकर लगाने के लिए टेंडर जारी कर राजस्व अर्जित किया जाए।पार्षदों को अधिकार दिए जाए और सीयर सफाई की जिम्मेदारी तय की

जाए।आफताब अहमद ने कहा कि शिक्षा संस्थानों के आसपास अशोभनीय बाते लिख दी जाती है।अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जाए। कानून सख्त किया जाए।सरकार योजना बनाकर कदम उठाए।नीयत स्थान पर ही पोस्टर स्टीकर लगाने की अनुमति दी जाए। गोयल ने सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है। विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के अंदर-अंदर मैगा सफाई अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध रूप से पोस्टर, स्टिकर व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई है, उसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार, नगरपालिका प्राधिकारी अर्थात नगर निगम के मामले में आयुक्त और नगर परिषद के मामले में कार्यकारी अधिकारी या सचिव की पूर्व अनुमति के बिना नगरपालिका सीमा के भीतर विज्ञापन करना प्रतिबंधित है। विपुल गोयल ने बताया कि इसके अतिरिक्त, सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में विज्ञापनों के कानूनी तरीके को विनियमित करने और अनुमति देने के उद्देश्य से 15 जुलाई,2022 को हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम 2022 अधिसूचित किया है। इन उपनियमों के तहत सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों की संपत्तियों पर विज्ञापन की अनुमति केवल खुली ई-नीलामी के माध्यम से दी जा सकती है, जिसके लिए 11 अक्टूबर,2022 को एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उपनियम 22 के अनुसार, अनधिकृत विज्ञापन हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत भी दंडनीय है।उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इसके अलावा, उपनियम 27 के तहत भारी जुर्माने (मासिक आधार पर लागू अनुमति शुल्क का तीन गुना) के प्रावधान किए गए हैं, साथ ही विज्ञापन एजेंसियों और संपत्ति मालिकों को तीन साल के लिए ब्लैकआऊट करने या पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। पिछले दो वित्तीय वर्षों 2023-24 और 2024-25 में नगर पालिकाओं से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को कुल 1915 नोटिस जारी किए गए हैं तथा कुल 3022 प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। इनमें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कुल 108334 पोस्टर , बिल , स्टिकर, विज्ञापन और पलेक्स हटाए गए हैं।

गांवों का विकास पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाये : संधवां

एजेंसी

फरीदकोट » पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने मंगलवार को कहा कि गांवों का विकास पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाये ताकि लोग बिना भेदभाव और गुटबंदी के नयी पंचायतों का सहयोग करें और गांवों के विकास में अपना योगदान दें। श्री संधवां ने आज नेहरू स्टेडियम, फरीदकोट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिले की कुल 241 ग्राम पंचायतों के 1653 पंचों को शपथ दिलाई, जिनमें ब्लॉक फरीदकोट के 788, ब्लॉक कोटकपूरा के 375 और ब्लॉक जैतो के 490 पंचायत सदस्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि नयी पंचायतें गांवों की दशा और दिशा बदल सकती हैं।

उन्होंने कहा कि नयी पंचायतों के सदस्य गांववासियों से सलाह-मशवरा करके और उपलब्ध फंड का सही तरीके से उपयोग करके गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करें। विधानसभा अध्यक्ष ने गांवों की गुटबंदी समाप्त करने की सलाह देते हुये कहा कि अब समय आ गया है कि पार्टीबाजी से ऊपर उठकर गांवों के साझा कार्य किये जायें और आम लोगों की जरूरतों के अनुसार काम किया जाये। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई और गांवों के समग्र विकास के लिये जनता के पैसे का समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिये।

गांवों के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी : भुल्लर

पब्लिक एशिया ब्यूरो

चंडीगढ़ » ज़िला तरन तारन के गाँवों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और बिना किसी पक्षपात के गाँवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। यह बात कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को पुलिस लाइन ग्राउंड तरन तारन में जिले की 568 पंचायतों के नए चुने गए 3882 पंचों को शपथ ग्रहण समारोह में संबोधित करते हुए कही।

. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंचायतें हमारे लोकतंत्र का मूल हैं और किसी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायतों की कार्यकुशलता बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज़िले की विभिन्न पंचायतों के नए चुने गए पंचों को बधाई देते हुए कहा कि वे मिलजुलकर अपने-अपने गाँवों के विकास के लिए निष्पक्ष होकर मेहनत करें और गाँवों में भाईचारक साझ को और मज़बूत बनाने का कार्य करें। भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए पंचायतों को फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने नए चुने पंचों और सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि गाँव के विकास में पंच-सरपंच की सबसे बड़ी भूमिका होती है और लोगों ने आप पर विश्वास जताया है, तो अब आपकी

जिम्मेदारी है कि लोगों के विश्वास को कायम रखा जाए।उन्होंने इस मौके पर पंचायत सदस्य बनीं महिलाओं को विशेष तौर पर बधाई दी और कहा कि वे पंचायत के कार्यों में सक्रियता से भाग लें।

इससे पहले हलका विधायक खेमकरण सरवन सिंह धुँन ने मुख्य अतिथि और समारोह में पहुंची अन्य शख्सियतों का स्वागत करते हुए पंचों और सरपंचों को शुभकामनाएँ दी। उन्होंने सभी पंचायतों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के गाँवों के विकास का जो सपना देखा है, उसे वास्तविकता में बदलने में पंचायतें अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि नए चुने गए पंच और सरपंच गाँवों के विकास में अधिकतम योगदान दें।

इस मौके पर हलका विधायक तरन तारन डॉ. कश्मीर सिंह सोहल ने अपने संबोधन में नए चुने गए पंचों-सरपंचों को बधाई देते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आज जो प्रण लिया है, उस पर पूरा उतरते हुए गाँवों के लोगों की सेवा करनी है और गाँवों के विकास में और तेजी लानी है। इस मौके पर हलका विधायक खडूर साहिब मनजिंदर सिंह लालपुरा ने कहा कि गाँवों के समुचित विकास में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज से पंचायतों का आधिकारिक काम शुरू हो रहा है और सरकार द्वारा धन की कमी नहीं आएगी और पंचायतें ये धन गाँवों में संजीदगी से खर्च कर गाँवों का समुचित विकास सुनिश्चित करेंगी।

आज विश्व शौचालय दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री . लालजीत सिंह भुल्लर ने ज़िले के योग्य लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के स्वीकृति पत्र भी जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर तरन तारन राहुल, चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट तरन तारन राजिंदर सिंह उसमां, चेयरमैन मार्केट कमेटी हरिके स. दिलबाग सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जनरल स. राजदीप सिंह बराड़, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विकास संजीव शर्मा, एसडीएम तरन तारन स. अरविंदरपाल सिंह, एसपी हेडक्वार्टर श्रीमती परविंदर कौर और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी स. हरजिंदर सिंह संधू सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। आज विश्व पाखाना शौचालय दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने ज़िले के योग्य लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के स्वीकृति पत्र भी जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर तरन तारन श्री राहुल, चेयरमैन नगर सुधार ट्रस्ट तरन तारन श्री राजिंदर सिंह उसमां सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।